

has completely been destroyed; more than 40 people died; 3.5 lakh livestock lost; 80,000 houses were totally or partially damaged and hundred of villages cut off due to overflowing of several rivulets and streams and breaches in tanks and canals. Almost all Mandals in these districts were under waist-deep water for several days and made the lives of the people agonizingly ordeal. The State Government could do very little due to the magnitude of "OGNI". Just to give an example, 273 mm of rain has been recorded in just two days. The State Government has requested the Centre for assistance. The Union Government sent a Central Team which had visited the affected areas on the 9th November, 2006, and submitted its report to the GoI for assistance. But, so far, nothing has been released by the GoI.

Hence, I request for immediately declaring "OGNI" as a national calamity and releasing Rs. 1,100 crores as relief to the State. I also request the GoI to help the State in getting Rs. 5,000 crores from the World Bank to repair the drainage system in the above districts. Thank, you, Sir.

Demand for inclusion of Gorkha Darjeeling Hill Council in the sixth schedule

श्री समन पाठक (पश्चिमी बंगाल): उपसभाध्यक्ष महोदय, पश्चिम बंगाल राज्य के अन्तर्गत स्थित दार्जीलिंग के तीन पहाड़ी अंचलों को लेकर दार्जीलिंग गोरखा पार्वत्य परिषद बनी थी। 23 अगस्त, 1988 से ही इसको संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने की मांग हमारी पार्टी सहित वहां की जनता करती आ रही है।

गत 6 दिसम्बर, 2005 के केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं दार्जीलिंग गोरखा पार्वत्य परिषद के प्रशासक के बची सम्पन्न हुई एक सभा में दार्जीलिंग गोरखा पार्वत्य परिषद को छठी अनुसूची में अन्तर्गुक्त करने का निर्णय लिया गया था। इसके आधार पर पश्चिम बंगाल विधान सभा से एक प्रस्ताव पारित कर केन्द्रीय सरकार के समक्ष भेजा गया है।

डी०जी०एच०सी० के निर्वाचित बोर्ड की मियाद खत्म हुए प्रायः 2 वर्ष हो चुके हैं। इसके फलस्वरूप यहां का विकासमूलक कार्य ठप्प है। यहां का जनसाधारण छठी अनुसूची लागू करने में विलम्ब महसूस कर रहा है। प्रायः 2 वर्ष से एक आदमी को लगातार प्रशासक बनाए रखना राज्य सरकार की बाध्यता है। तथापि एक व्यक्ति को बार-बार प्रशासक बनाकर रखना केवल दार्जीलिंग की जनता के लिए ही नहीं, बल्कि सम्पूर्ण गणतान्त्रिक ढांचे के लिए उचित नहीं है। राजनीतिक अस्थिरता के कारण यहां के नौजवान चरम हताशा-ग्रस्त हो चुके हैं। जिसके फलस्वरूप विभिन्न अगणतान्त्रिक शक्तियों द्वारा जनता को कुपथ में ढकेलने की आशंका दिखाई दे रही है, जिसके चलते यहाँ की शांति-श्रृंखला भंग होने की आशंका है।

महाशय, इसके लिए मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि यथाशीघ्र छठी अनुसूची लागू करने का विधेयक संसद में प्रस्तुत कर दार्जीलिंग गोरखा पार्वत्य परिषद को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की जाए।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Shri Pyarelal Khandelwal, not here; Shri Ajay Maroo, not here; Shri Thanga Tamil Selvan, not here; Shri Rudra Narayan Pany, not here; Shri R. Shunmugasundaram, not here; and, Shri Mahendra Mohan, not here.

The House stands adjourned to meet at 11.00 a.m. on Monday, the 27th November, 2006.

The House then adjourned at twelve minutes past five of the clock till eleven of the clock on Monday, the 27th November, 2006.